RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 286
दि. 17.02.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

इंडिया एआई समिट में जियो पवेलियन पहुंचे पीएम मोदी, आकाश अंबानी ने दिखाए भविष्य के मॉडल

(जीएनएस)।

नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में तकनीक की नई झलक देखने को मिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियो के अक पवेलियन का दौरा किया. यहां हेल्थ, शिक्षा और स्मार्ट होम से जुड़े आधुनिक मॉडल पेश किए गए. दौरे ने भारत में अक के बढ़ते दायरे और संभावनाओं को उजागर किया.

जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने इंडिया अक इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान जियो अक पवेलियन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हेल्थकेयर, एजुकेशन, कल्चर और स्मार्ट होम सॉल्यूशंस में कंपनी के अक-लेड ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया.

नई दिल्ली में आयोजित India AI Impact Summit 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियो इंटेलिजेंस पवेलियन का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कई अत्याधुनिक मॉडलों और समाधानों की लाइव प्रस्तुति देखी. यह दौरा भारत में तेजी से बढ़ते अक इकोसिस्टम और निजी क्षेत्र की भूमिका को रेखांकित करने वाला माना जा रहा है. आकाश अंबानी ने दिखाई अक की पूरी झलक, जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी को जियो के व्यापक अक इकोसिस्टम के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कैसे कंपनी का अक स्टैक एंटरप्राइज इंटेलिजेंस से लेकर स्मार्ट होम तक समाधान दे रहा है. प्रधानमंत्री ने Jio AI Stack, Jio Sanskriti AI, Jio Arogya AI, Jio Shiksha और Jio AI Home जैसी पहलों का अवलोकन किया. ये प्लेटफॉर्म भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक कंटेंट को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और स्मार्ट जीवनशैली को सक्षम बनाने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं. हेल्थ, शिक्षा और संस्कृति में अक की ताकत, पवेलियन में प्रदर्शित मॉडलों ने दिखाया कि अक किस तरह अस्पतालों में बेहतर निदान, स्कूलों में पर्सनलाइज्ड लर्निंग और भारतीय भाषाओं के संरक्षण में मदद कर सकता है. जियो का फोकस ऐसी तकनीक विकसित करना है जो सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव और छोटे कस्बों तक भी पहुंचे. कंपनी ने 'AI for All' के अपने विजन को दोहराते हुए कहा कि उन्नत तकनीक को सुलभ और समावेशी बनाना ही असली डिजिटल परिवर्तन है.

निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका

Reliance Jio Innocomm Limited और इसकी मूल कंपनी Reliance Industries पहले भी तकनीक को जनसामान्य तक पहुंचाने पर जोर देती रही हैं. उद्योग जगत के नेताओं का मानना है कि भारत का अक भविष्य सार्वजनिक और निजी साझेदारी से ही मजबूत होगा. समिट में देश-विदेश की टेक कंपनियां, इनोवेटर्स और नीति-निमार्ता शामिल हुए, जिससे साफ है कि भारत वैश्विक अक मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है. प्रधानमंत्री का यह दौरा इसी दिशा में एक अहम संकेत माना जा रहा है.

यूपी में फॉर्म 7 पर मची सियासी रार के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार, पूछा- इस पर चिल्लाहट क्यों?

यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के बीच फॉर्म 7 पर जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद् में इस पर जवाब दिया और सपा पर पलटवार किया.

(जीएनएस)।

भारत निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार उत्तर प्रदेश में जारी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 के दुरुपयोग का दावा किया है. अब इस पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है.

कांग्रेस का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने पूछा कि आखिर इसमें इतनी चिल्लाहट क्यों मच रही है. उन्होंने कहा कि सपा को कांग्रेस से सबक लेना चाहिए. आज विधान परिषद् में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है. अगर यही स्थिति रही तो सपा भी यहां शून्य हो जाएगी.

सीएम योगी ने कहा कि विपक्षी दल हमारे संवैधानिक मूल्यों पर प्रहार करने से नहीं चूक रहे. वर्तमान में प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है. इसमें राज्य सरकार की कोई

भूमिका नहीं होती. आयोग जो गाइडलाइन जारी करता है उसके अनुसार तंत्र उसका पालन करता है लेकिन सरकार उसका हिस्सा नहीं होती.

यूपी में रक्क पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा चीफ ने कहा- फर्जी साइन से वोट कटवा रही इखढ

सीएम ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में 2 करोड़ लोग 88 लाख से अधिक लोग या तो अनुपस्थित पाए गए या मृत पाए गए या फिर शिफ्ट हो गए. हमें आश्चर्य होता है कि सपा इनको अपना वोट बैंक बनाकर फर्जी वोटिंग कराती है. इसीलिए चिल्ला रही है कि फॉर्म 7 के नाम पर फर्जी काम हो रहा है.

सीएम योगी ने कांग्रेस का नाम लेकर कसा सपा पर तंज

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक व्यवस्था बनाई है. तीन प्रकार के फॉर्म दिए गए हैं.जिसमें फॉर्म, 6,7 और 8. फॉर्म 6 में आपको मतदाता होने का प्रमाण या नाम जुड़वाने के लिए देना होता है. फॉर्म 7 में अगर किसी का नाम कटवाना है तो उसका इस्तेमाल होता है. अगर कोई व्यक्ति भौतिक रूप से उपस्थित हो जाता है तो वह फॉर्म स्वतः निरस्त हो जाता है. मैं नहीं समझता कि आखिर इस पर इतनी चिल्लाहट क्यों हो रही है? आरोप प्रत्यारोप क्यों लग रहे हैं. यह नहीं हो सकता है कि हम अपने अनुरूप संवैधानिक संस्थाओं की परिभाषा गढ़ें.

सीएम ने इस दौरान कांग्रेस का नाम लेते हुए कहा कि मैं सपा से कहूंगा कि वह कम से कम कांग्रेस से सबक लें. विधान परिषद् तो कांग्रेस विहीन हो गया है. अगर आपको यहां और विधानसभा में सपा विहीन बनना है तो इस तरह के अनर्गल प्रलाप करते रहिए.

राष्ट्रपति ने अलचिकि लिपि के शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (16 फरवरी, 2026) नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित अलचिकि लिपि के शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि संताल समुदाय की अपनी भाषा, साहित्य और संस्कृति है। हालांकि, अपनी लिपि के अभाव में संताली भाषा को प्रारंभ में रोमन, देवनागरी, उड़िया और बंगाली लिपियों में लिखा जाता था। नेपाल, भूटान और मॉरीशस में रहने वाले संताल समुदाय के लोग भी वहाँ प्रचलित लिपियों का उपयोग करते थे। ये लिपियां संताली भाषा के मूल शब्दों का सही उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पा रही थीं. साल 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मु ने अलचिकि लिपि का आविष्कार किया। तब से यह संताली भाषा के लिए उपयोग में लाई जा रही है। आज यह लिपि विश्वभर में संताल पहचान का सशक्त प्रतीक बन चुकी है और समुदाय में एकता स्थापित करने का प्रभावी माध्यम भी है।

पीएम मोदी संसद में बोलने से बचते हैं, इंटरव्यू 'खोखले शब्दों' के अलावा कुछ नहीं : डेरेक ओ'ब्रायन

(जीएनएस)।

नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीटीआई को दिए उनके इंटरव्यू को लेकर सोमवार को निशाना साधते हुए उन्होंने इसे "खोखले शब्द" बताते हुए कहा कि वह संसद में बोलने के बजाय "भाग गए".

राज्यसभा में टीएमसी के नेता ओ'ब्रायन ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए उन्हें ह्यह्यटेलीप्रॉम्प्टर टाइकूनह्लह्ल भी कहा. ओ'ब्रायन ने इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया देते हुए पीटीआई-भाषा से कहा, ह्यह्यप्रधानमंत्री मोदी यानी ह्यटेलीप्रॉम्प्टर टाइकूनह्ल के खोखले शब्दों का एक और उदाहरण..., जो संसद में बोलने से कतराते हैं.ह्लह्ल

बता दें कि हाल में बजट सत्र के दौरानअभूतपूर्व घटनाक्रम में, विपक्षी सदस्यों की लगातार नारेबाजी के दौरान, लोकसभा ने प्रधानमंत्री के पारंपरिक उत्तर दिए बिना ही, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव

को पारित कर दिया था.

वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बाद में कहा कि उनके पास पुख्ता जानकारी थी कि कांग्रेस के कई सदस्य प्रधानमंत्री मोदी की सीट की ओर बढ़ सकते हैं और किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम दे सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उनसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने के लिए सदन में नहीं आने का अनुरोध किया था. राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के बाद पीएम मोदी ने जवाब दिया था. इस दौरान विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया था. पीएम ने रविवार को नवीनतम बजट और अपनी सरकार द्वारा हस्ताक्षरित कई वैश्विक व्यापार समझौतों को विकसित भारत की नींव बताया था और निजी क्षेत्र से अब अधिक आक्रामक और साहसिक रूप से आगे आने का अनुरोध किया.

पीटीआई को दिए इंटरव्यू में, पीएम ने अहम व्यापार समझौतों को हासिल करने में विफल रहने के लिए पूर्ववर्ती संप्रग सरकार की कड़ी आलोचना की. साथ ही जोर देकर कहा कि विकसित भारत में महिलाएं सबसे अहम भूमिका निभाएंगी.

भारतीय व्यापार सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, रक्षा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन सेवा और भारतीय व्यापार

सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।

राष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिष्ठित सेवाओं में चयन से उन्हें राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मिलता है। उन्होंने उन्हें यह याद रखने की सलाह दी कि ऐसे बहुत से युवा हैं जो ये सेवा करने का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है।

भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में आयोजित अभ्यास मिलन 2026 के अंतर्गत मिलन विलेज का उद्घाटन किया

(जीएनएस)।

भारतीय नौसेना ने अपने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 के अंतर्गत 15 फरवरी 2026 को पूर्वी नौसेना कमान में मिलन विलेज का अनावरण किया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता वाइस एडमिरल संजय भल्ला, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी नौसेना कमान ने की। उन्होंने भाग लेने वाली मित्र नौसेनाओं के लिए औपचारिक रूप से मिलन विलेज का शुभारंभ किया और वैश्विक समुद्री सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु विकसित की गई सुविधाओं का निरीक्षण किया।

काफी विचार-विमर्श व सोच-समझ के बाद विकसित किया गया मिलन विलेज एक विशिष्ट अनुभव क्षेत्र है, जिसे 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और नौसेना कर्मियों को सौहार्द एवं मित्रता के वातावरण में एक साथ लाने के उद्देश्य से परिकल्पित व निर्मित किया गया है। यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान का केंद्र है, जो पेशेवर सीमाओं से आगे बढ़कर आपसी जुड़ाव और समझ को सशक्त बनाता है।

मिलन विलेज की एक प्रमुख विशेषता सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर इसका विशेष बल है, जो भारत की विविधतापूर्ण विरासत और परंपराओं की समृद्ध एवं जीवंत झलक प्रस्तुत करता है। यह गांव गायकों की सजीव प्रस्तुतियों, पारंपरिक लोक नृत्य कार्यक्रमों और विभिन्न सांस्कृतिक समूहों की मेजबानी करेगा, जो भारत की जीवंत व बहुरंगी कलात्मक विरासत को प्रदर्शित करेंगे।

मिलन विलेज में नौसेना से संबंधित स्मृति चिन्हों के साथ-साथ हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों की अनेक दुकानें स्थापित की गई हैं, जो देशभर की समृद्ध कारीगरी का सुंदर प्रदर्शन करती हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू पर कांग्रेस संचार प्रभारी जयराम रमेश का वार कहा, बजट और ट्रेड डील से ध्यान भटकाने की कोशिश

(जीएनएस)।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के पीटीआई साक्षात्कार को "हताश पीआर कवायद" बताया है। कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे 'सावधानीपूर्वक लिखी गई और हताश पीआर कवायद" करार दिया है। पार्टी का आरोप है कि यह इंटरव्यू वास्तविक सवालों से बचने और सुर्खियां प्रबंधित करने का प्रयास है।

कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री व्यापार समझौते और बजट को लेकर विपक्ष के हमलों से घिरे हुए हैं, इसलिए वह अपने पसंदीदा हथकंडे यानी हेडलाइन मैनेजमेंट का सहारा ले रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि इस वर्ष का बजट निराशाजनक रहा है और बाजार व निवेशकों की प्रतिक्रिया भी उत्साहजनक नहीं रही।

ध्यान हटाने की कोशिश

जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि

प्रधानमंत्री किसानों और अन्य वर्गों से जुड़े मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह कोई इंटरव्यू नहीं बल्कि एक सोचा-समझा प्रचार अभ्यास है।

व्यापार वार्ता पर मोदी के आरोपों को बताया 'अनुचित और गलत'

प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान व्यापार वाताओं की आलोचना किए जाने पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए उनके आरोपों को 'अनुचित और गलत" करार दिया है। पार्टी का कहना है कि यूपीए शासन में भारत ने एक आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में कई महत्वपूर्ण व्यापार समझौते किए थे।

पूर्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने बयान जारी कर कहा कि यूपीए काल में भारत की अर्थव्यवस्था ने औसतन आठ प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर्ज की और 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद भी मजबूती से उभरी। उन्होंने मौजूदा सरकार द्वारा अमेरिका के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते को 'अपारदर्शी" बताते हुए उसके विवरण सार्वजनिक करने की मांग की। उनका आरोप है कि कृषि, कपास और वस्त्र जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

भिवाड़ी अग्निकांड के मृतकों के परिजनों को राजस्थान सरकार देगी 3-3 लाख रुपये मुआवजा

(जीएनएस)।

भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग से हुई जनहानि को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने "अत्यंत हृदयविदारक और दुखद" बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुःख की इस घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूरी संवेदना से खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से तीन-तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन को भी प्रत्येक पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता तत्काल सुनिश्चित करने को कहा गया है।

अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र की इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है, और राज्य सरकार ने पीड़ितों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।

भिवाड़ी में कैसे हुआ ये हादसा?

बता दें राजस्थान के भिवाड़ी में सोमवार को एक रासायनिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से सात श्रमिकों की मौत हो गई। इस हादसे में दस अन्य मजदूरों के अभी भी फंसे होने की आशंका जताई गई थी। यह घटना सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे हुई, जब फैक्ट्री में 20-25 कर्मचारी काम कर रहे थे।

चंद मिनटों में विकराल हो गई थी आग

आग कुछ ही मिनटों में निजी औद्योगिक इकाई से तेजी से फैल गई और फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ श्रमिक अपनी जान बचाने में सफल रहे। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुमिता मिश्रा ने बताया, घटना का पता पुलिस की नियमित गश्त के दौरान चला।

पुलिस, दमकल कर्मी, मेडिकल टीमें और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत प्रयासों के लिए क्षेत्र को घेर लिया। डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया।

हालांकि, आग लगने के सटीक कारणों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। तिजारा के पुलिस उपाधीक्षक शिवराज सिंह घटनास्थल पर प्रारंभिक जांच की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक और अपर जिला मजिस्ट्रेट सहित वरिष्ठ जिला अधिकारी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।

जिला प्रशासन ने आग के कारणों और सुरक्षा प्रोटोकॉल में संभावित चूकों का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रियल जांच की घोषणा की है।

सम्पादकीय

बीएलए के समक्ष पस्त हो रही पाक सेना

पाकिस्तान की आर्मी इतनी बहादुर है कि जब बीएलए यानि बलोच लिबरेशन आर्मी चाहती है, उन्हें ठोंकती है और नाक रगड़वा कर छोड़ती है। तालिबान सरकार को जब गुस्सा आता है तो वह अपने लड़ाकों को भेजकर पीटती है और दर्जनों जब मारे जाते हैं तो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुल्ला आसिम मुनीर अरब देशों से गुहार लगाता है कि हमें बख्श दो अब गलती नहीं होगी, लेकिन झुठे नैरेटिव गढ़ने के ये इतने चतुर शिल्पी हैं कि भारत के साथ जितनी लड़ाइयां हुई, उन सभी में जीत का दावा करते हैं और बाजार से खरीद कर सैन्य अधिकारी तमगे लगा लेते हैं। पोल पट्टी खुलने के डर से इस झुठ को फर्जी रूप से सही बनाने के लिए स्थाई भाव की जो साजिश रची गई है, उसी के तहत 1965, 1971 और कारगिलद्वास बटालिक युद्ध को जीतने का दावा अपने बच्चों की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है और यदि कोई पत्रकार हिम्मत करके सवाल पूछ लेता है तो उसे सैन्य प्रतिष्ठान न सिर्फ धमकाता है बल्कि उसको तरह-तरह से प्रताड़ित किया जाता है। अब इनकी सेना की वास्तविकता यह है कि इनके 17 सैनिकों को बीएलए ने हिरासत में ले लिया और 10 सैनिकों को मुक्त करके सैन्य प्रतिष्ठान को चेतावनी दी है कि यदि 7 और सैनिकों को छुड़ाना है तो उनके कैदियों को एक सप्ताह के अन्दर रिहा करो।

सच तो यह है पाकिस्तान का जैसा चरित्र है, वैसी ही उसकी फौज भी है। वह कुरान की कसम खाकर जान तो बीएलए से कई बार बचा चुकी है किन्तु अब बीएलए उनके झांसे में नहीं आती इसलिए अब सेना और बीएलए में जो भी सौदेबाजी होती है, वह 'एक हाथ से दे और दूसरे हाथ से ले' के सिद्धांत पर होती है। गत वर्ष जब पाक ट्रेन को ही ब्लूचिस्तान में बीएलए ने अपहरण किया था तब भी सेना अपने बल पर अपने साथियों को छुड़ा नहीं पाई थी। आए दिन पाक सेना खासकर पंजाब प्रांत के जवानों को बीएलए के लोग पीटते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पाक सेना अपने पड़ोसियों से पिटती है तो बाप-बाप चिल्लाती है और 'सीज फायर' के लिए गिड़गिड़ाने लगती है लेकिन शेखी ऐसी बघारते हैं कि वह युद्ध तो किसी देश से हारते ही नहीं, अपने देश की जनता को पाकिस्तान की सेना यह बताती है कि ब्लुचिस्तान में जो गड़बड़ चल रही है, उसके लिए भारत जिम्मेदार है। वह वास्तविकता को महसूस करने के लिए तैयार ही नहीं है। कल्पना करें, यदि भारत ब्लुचिस्तान में अलगाववादी गतिविधियां कराता तो क्या अभी तक पाकिस्तान का विखंडन न हो गया होता! वास्तविकता यह है कि बीएलए ईरान से अवैध तेल हासिल कर उनसे धन कमाते हैं और पाकिस्तान की सेना को तबाह करते हैं। यही नहीं बीएलए चीन से भी उगाही करके उन्हें ब्लूचिस्तान में काम करने की अनुमति देता है। उसको मोटी कमाई हो रही है। इसलिए जब जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने अमेरिका को कच्चे तेल और अपना रेयर अर्थ मिनरल निकालने का आग्रह किया तब बलोच मुक्ति आंदोलन के नेताओं ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वह जनरल मुनीर और प्राधानमंत्री शरीफ पर भरोसा न करें क्योंकि आप बीएलए से लड़कर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। पाक सेना बीएलए से आप के लोगों को सुरक्षा भी नहीं दे पाएगी। इसलिए यदि खनिज उत्खनन में आप कुछ करना चाहते हैं तो बीएलए से समझौता कर ले। इस पत्र के बाद ही ट्रंप का माथा ठनका था। यही कारण है आजकल ट्रंप पाकिस्तान को उस तरह चने की झाड़ पर नहीं चढ़ाता जैसा कि 2025 में अपने पूरे परिवार को पाकिस्तान में खनिज हासिल करने की उम्मीद से काम पर सक्रिय कर दिया था। बहरहाल पाकिस्तान की आमा इतनी जाहिल हो चुकी है कि वह कभी भारत से पिटती है तो पीठ झाड़ कर दावा करती है कि उसने तो मैदान मार लिया, बीएलए सैनिकों को ही मारती है इसलिए पाकिस्तान सहित सारे क्षेत्रों के सैनिक बीएलए से पिटने के बाद भी खुलकर यह मानने को तैयार नहीं हैं कि ब्लूचिस्तान में अलगाववाद की आंधी यू ही नहीं आई है, इसका मुख्य कारण है बलूचों की समस्याओं को सुने बिना ही उन्हें आतंकी घोषित कर दिया गया। बलूचों का समस्या है कि उनके मासूम बच्चों और पुरुषों को पाक सेना मारती है और गायब कर देती है।

तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे पीएम मोदी, उनकी जगह भारत से ये नेता होंगे शामिल

(जीएनएस)। भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिसरी 17 फरवरी को तारिक रहमान के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

भारत के विदेश मंत्रालय और बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मीडिया सेल ने इसकी पुष्टि की है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, "लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 17 फरवरी 2026 को ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान के नेतृत्व में बनी नव-निर्वाचित बांग्लादेश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे।"

इस बयान में आगे कहा गया है, "लोकसभा अध्यक्ष की इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भागीदारी भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच गहरी और स्थायी मित्रता को रेखांकित करती है. यह उन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि भी है, जो हमारे दोनों देशों को जोड़ते हैं."

"साझा इतिहास, संस्कृति और परस्पर सम्मान से जुड़े पड़ोसी देशों के रूप में, भारत तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश के एक निर्वाचित सरकार की ओर बढ़ने का स्वागत करता है, जिनकी सोच और मूल्यों को बांग्लादेश की जनता ने भारी जनादेश दिया है."

बांग्लादेश के तेरहवें संसदीय चुनाव में बीएनपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे।

बांग्लादेश में नए कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने 13 देशों के शासनाध्यक्षों को आमंत्रित किया है।

ढाका में मौजूद बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित के अनुसार, अब तक जिन देशों को आमंत्रण भेजा गया है, उनमें चीन, सऊदी अरब, भारत, पाकिस्तान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान शामिल हैं।

इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों कल यानी 16 फरवरी से भारत की यात्रा पर आ रहे हैं।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने मैक्रों के दौरे का पूरा शेड्यूल जारी किया है जिसमें वो 16 फरवरी को देर रात दिल्ली पहुंच रहे हैं और 17 फरवरी को उनका मुंबई में कार्यक्रम है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में मैक्रों के साथ होंगे, जहां राजभवन के दरबार हॉल में एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे और प्रेस बयान जारी किया जाएगा।

मैक्रों का दौरा 19 फरवरी तक रहने वाला है और वो शाम को पेरिस रवाना होंगे।

इसलिए कुछ लोग अनुमान लगा रहे थे कि अंतराष्ट्रीय दौरे की व्यस्तता के चलते पीएम मोदी शायद तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में न जा पाएं। हालांकि भारत की तरफ से खबर लिखे जाने तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

शुक्रवार को चुनाव के नतीजे आने के बाद पीएम मोदी ने तारिक रहमान को फोन कर चुनाव में जीत के लिए बधाई भी दी थी। बीएनपी ने पीएम मोदी को इसके लिए शुक्रिया भी कहा है।

बीबीसी बांग्ला संवाददाता शुभज्योति घोष ने शनिवार को पुष्टि की थी कि बीएनपी के चेयरपर्सन ऑफिस ने शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी को भी आमंत्रण भेजे जाने की जानकारी दी है।

बीएनपी अध्यक्ष के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर हुमायूं कबीर ने भी पुष्टि की थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तारिक के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा।

हालांकि अभी तक भारत की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद भारत ने बीएनपी के साथ संवाद के रास्ते खोले हैं। बीएनपी की जीत पर बधाई देने वाले शुरुआती नेताओं में पीएम मोदी रहे हैं।

तारिक रहमान ने भी रचनात्मक रूप से भारत के साथ बहुआयामी रिश्ते को मजबूत करने पर जोर दिया है।

शपथ ग्रहण के सवाल पर बीएनपी के नेता एएनएम एहसानुल हक ने शनिवार को ढाका में पत्रकारों के साथ बातचीत में उम्मीद जताई थी कि पीएम मोदी को आमंत्रण दिया जाएगा।

दक्षिण एशिया के नेताओं को आमंत्रित करने के सवाल पर उन्होंने कहा, "मुझे ठीक ठीक तो नहीं पता है लेकिन उम्मीद है कि वे सभी को बुलाएंगे। पीएम मोदी को भी बुलाया जाना चाहिए. ये एक सामान्य शिष्टाचार है और आयोजक ऐसा करेंगे।"

बीएनपी ने अपने चुनावी अभियान में 'सभी से मित्रता' की नीति का वादा किया था।

पहले भी बीएनपी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से संकेत दिया गया था कि शपथ ग्रहण समारोह में सार्क (दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन) देशों के नेताओं को आमंत्रण भेजा जाएगा, जिनमें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का भी नाम होगा।

साल 2014 में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद सार्क देशों के नेताओं का ऐसा जुटान, पहली बार ढाका में होने की संभावना जताई जा रही है.

रक्षा मंत्री ने बेंगलुरु में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान में स्वदेशी सैन्य गैस टरबाइन इंजन विकास परियोजनाओं की समीक्षा की

राष्ट्रीय सुरक्षा को आत्मनिर्भरता के माध्यम से मजबूत करने के लिए जीटीआरई की सराहना की

सरकार एयरो इंजन विकास में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है

ऑपरेशन सिंदूर ने रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया है, विश्व स्तरीय स्वदेशी प्रणालियों के निर्माण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 6 फरवरी, 2026 को बेंगलुरु स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान (जीटीआरई) का दौरा किया और स्वदेशी सैन्य गैस टरबाइन इंजन विकास से सम्‍बंधित परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री को प्रतिष्ठान की निमार्णाधीन परियोजनाओं, भारतीय उद्योग, शिक्षा जगत और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ हुए संवाद और रक्षा बलों को प्रदान किए जा रहे समर्थन के बारे में जानकारी भी दी गई। उन्होंने विभिन्न स्वदेशी इंजनों और उनके पुर्जों की प्रदर्शनी का भी दौरा किया और कावेरी इंजन के पूर्ण आफ्टरबर्नर परीक्षण को देखा।

रक्षा मंत्री ने वैज्ञानिकों और अधिकारियों से बातचीत करते हुए आत्मनिर्भरता से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के लिए जीटीआरई की सराहना की और डीआरडीओ को देश की रणनीतिक क्षमता का आधार बताया। उन्होंने वर्तमान तेजी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में एयरो इंजन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के महत्व पर बल दिया और कहा कि देश में एयरो इंजनों के विकास को प्राथमिकता देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं में परिवर्तन आ रहा हैं और नए इकोसिस्‍टम विकसित हो रहे हैं। स्वदेशी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों वाले राष्ट्र सुरक्षित, संरक्षित और आत्मनिर्भर बने रहेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रत्‍येक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को दोहराया।

जीटीआरई के महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्र में हुए प्रयासों के बारे में श्री राजनाथ सिंह ने प्रयोगशाला से आग्रह किया कि वह एक राष्ट्रव्यापी मजबूत इकोसिस्‍टम का निर्माण करते हुए अगली पीढ़ी के इंजनों पर ध्यान केंद्रित करे और साथ ही एयरो इंजनों में आत्मनिर्भरता हासिल करे। उन्होंने यह भी कहा कि हम उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (एएमसीए) के डिजाइन और विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने अतीत में एयरो इंजनों के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के कई प्रयास किए हैं। अब उन प्रयासों को पूरा करने का समय आ गया है। हम खुद को केवल पांचवीं पीढ़ी के इंजनों तक सीमित नहीं रख सकते । हमें जल्द से जल्द छठी पीढ़ी की उन्नत तकनीकों का विकास शुरू करना होगा। इन पर शोध समय की मांग है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और नई सामग्रियों का उपयोग बढ़ रहा है। हमें इस क्षेत्र में अग्रणी बने रहना होगा।

रक्षा मंत्री ने एयरो इंजन के विकास को एक अत्यंत जटिल कार्य बताया। इसमें ऊष्मागतिकी, पदार्थ विज्ञान, द्रव यांत्रिकी और उन्नत यांत्रिक अभियांत्रिकी का समावेश होता है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों को भी अगली पीढ़ी के इंजन विकसित करने में अक्सर 25-30 साल लग जाते हैं, और उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों से देश की रणनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समयसीमा को कम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमें यह मानकर चलना होगा कि 20 साल बीत चुके हैं और अब हमारे पास केवल 5-7 साल बचे हैं। उन्होंने इसे राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप कार्रवाई का आह्वान बताया।

ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान रक्षा बलों ने रक्षा क्षेत्र में देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि संचार प्रणाली हो, निगरानी उपकरण हों या आक्रमण हथियार, सब कुछ स्वदेशी था। इससे हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ा और नागरिकों में गर्व की भावना पैदा हुई। बदलती चुनौतियों को देखते हुए, स्वदेशी पद्धतियों पर अधिक ध्यान देना और अपनी सेनाओं को विश्व स्तरीय प्रणालियां और उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

रक्षा मंत्री ने एयरो इंजन विकास के लिए ब्रिटेन के साथ संयुक्त अध्ययन की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय एयरो इंजन मिशन के तहत फ्रांस के साथ भी एयरो इंजन के लिए यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही एयरो इंजन प्रौद्योगिकी में काफी उन्नत हैं। ये सहयोग न केवल हमें नई प्रौद्योगिकियों को सीखने का अवसर प्रदान करेंगे, बल्कि पिछले दशकों में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को समझने में भी मदद करेंगे।

आधार ऐप की बढ़ती लोकप्रियता और दैनिक उपयोगिता, ऐप के माध्यम से 1 मिलियन लोगों ने घर बैठे मोबाइल नंबर अपडेट किया

यूआईडीएआई के आधार ऐप को मिली शानदार प्रतिक्रिया, डाउनलोड्स की संख्या 14 मिलियन के पार

आधार ऐप डेटा मिनिमाइजेशन, कंसेंट कंट्रोल और सेलेक्टिव शेयरिंग जैसी कई प्रमुख विशेषताओं को बढ़ावा देता है

(जीएनएस)। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआइई) के नए आधार ऐप को लेकर आम जनता में भारी उत्साह देखा जा रहा है। ऐप को अपनाने की यह तेज गति सुरक्षित, डिजिटल और सुविधाजनक आधार सेवाओं के प्रति नागरिकों के बढ़ते भरोसे को दशार्ती है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआइई) के नए आधार ऐप ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब तक इसे लगभग 14 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। यह सफलता देश भर में आधार सेवाओं को अधिक सुलभ, उपयोगकर्ता के अनुकूल और तुरंत उपलब्ध कराने में इस ऐप की महत्वपूर्ण भूमिका को दशार्ती है।

आधार ऐप एक नेक्स्ट-जेनरेशन का मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसे आधार संख्या धारकों (एएनएच) को अपनी डिजिटल पहचान रखने, साझा करने, दिखाने और सत्यापित करने के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और गोपनीयता-केंद्रित तरीका प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एंड्रॉइड और एप्पल आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

28 जनवरी को राष्ट्र को समर्पित किए गए इस नए ऐप को औसतन प्रतिदिन 1,00,000 से अधिक लोग डाउनलोड कर रहे हैं। इस ऐप की बढ़ती उपयोगिता ने आधार सेवाओं को निवासियों के लिए घर बैठे ही सुलभ बना दिया है। अब तक यह ऐप 1 मिलियन निवासियों को अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने में मदद कर चुका है। वहीं 3,57,000 आधार धारकों ने ऐप के जरिए अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक या अनलॉक किया है। इसी तरह, लगभग 8,00,000 निवासियों ने नए ऐप का उपयोग करके अपना ई-आधार डाउनलोड किया है।

इस ऐप में कई आधुनिक और उन्नत सुविधाएँ शामिल हैं, जैसे प्रेजेंस के प्रूफ के तौर पर फेस वेरिफिकेशन, सिंगल क्लिक में बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक, ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को देखने की सुविधा और कॉन्टैक्ट डिटेल्स को आसानी से साझा करने के लिए दफ-आधारित कॉन्टैक्ट कार्ड।

सभी यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया यह आधार ऐप, दैनिक जीवन के कई महत्वपूर्ण कार्यों में सहायक है। इसके माध्यम से होटल में चेक-इन के दौरान ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटी (ओवीएसई) क्यूआर कोड स्कैनिंग, उम्र का सत्यापन, अस्पतालों में भर्ती, कार्यक्रमों में प्रवेश और गिग वर्कर्स व सर्विस पार्टनर्स के सत्यापन जैसे कई कार्य सुगम हो गए हैं। इसके साथ ही, यूआईडीएआई एक ऐसा ऑफलाइन वेरिफिकेशन इकोसिस्टम भी विकसित कर रहा है, जिससे विभिन्न संस्थाएं पंजीकृत होकर आधार ऐप की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगी और सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाया जा सकेगा।

यह ऐप एक ही डिवाइस पर पांच आधार प्रोफाइल तक के प्रबंधन की

सीएक्यूएम ने 2026 में गेहूं की पराली जलाने की समस्या को खत्म करने के लिए कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में व्यापक वैधानिक निर्देश जारी किए

(जीएनएस)। एनसीआर और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने वैधानिक निर्देश जारी किए हैं, जिसमें 2026 की कटाई के मौसम के दौरान गेहूं की पराली को जलाने की रोकथाम और उसकी समस्या को खत्म करने के लिए राज्य कार्य योजनाओं के समन्वित और समयबद्ध कार्यान्वयन को जरूरी बताया गया है। यह निर्देश पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को जारी किए गए हैं, और इसके साथ-साथ जीएनसीटीडी और राजस्थान से भी मदद की अपेक्षा की गई है।

आयोग ने कहा कि कृषि अवशेष जलाने से स्थानीय स्तर पर तथा एनसीआर एवं आस-पास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है, इसलिए इसके लिए क्रमबद्ध तरीके से मौसमी तैयारी की आवश्यकता है। इसरो/आईएआरआई द्वारा स्थापित मानक प्रोटोकॉल के अनुसार, गेहूं की कटाई के मौसम (1 अप्रैल से 31 मई 2025) के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों में आग की घटनाओं की संख्या क्रमशः 10207, 1832 और 259 रही। गेहूं की कटाई के मौसम (अप्रैल-मई 2025) के दौरान उपग्रह-आधारित मॉनिटरिंग में पूरे क्षेत्र में आग लगने की ऐसी घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया, जिससे धान के मौसम के मौजूदा उपायों के साथ-साथ गेहूं के मौसम में लक्षित उपायों की आवश्यकताओं पर जोर दिया गया।

आयोग ने फसल अवशेष जलाने को नियंत्रित/समाप्त करने के लिए संबंधित राज्यों को एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की थी और उन्हें रूपरेखा के मुख्य हिस्सों के आधार पर विस्तृत राज्य-विशिष्ट कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, गेहूं की पराली जलाने के मुद्दे पर 22 दिसंबर, 2025 को आयोग की 26वीं बैठक और उसके बाद पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ हुई बैठकों में विस्तार से चर्चा की गई थी, जहां राज्य सरकारों ने अपनी कार्ययोजना पेश की और आयोग ने इन राज्यों को अपनी कार्य-योजनाओं को और बेहतर बनाने की सलाह दी।

तदनुसार, आयोग ने अपनी निर्देश संख्या 96 के माध्यम से, संबंधित राज्यों को व्यवहारिक विकल्प सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट सुविधाजनक उपायों के साथ गेहूं के भूसे को जलाने को रोकने के लिए अपनी संबंधित कार्य योजनाओं को कार्यान्वित करने का निर्देश दिया है। आयोग ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को निर्देश दिया है किः गेहूं की पराली जलाने की समस्या को खत्म करने

डिजाइन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर आधारित चिप डिजाइन स्टार्टअप्स पर बड़े निवेशकों का फोकस जारी

सी2आई सेमीकंडक्टर्स ने पीक एक्सवी पार्टनर्स के नेतृत्व में 15 मिलियन डॉलर की सीरीज फंडिंग जुटाई - किसी भारतीय सेमीकंडक्टर स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई अब तक की सबसे बड़ी फंडिंग

सी2आई ऊर्जा कुशल और विश्वसनीय उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए इंटेलिजेंट पावर-मैनेजमेंट चिप डिजाइन कर रही है

(जीएनएस)। भारत का सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना के अंतर्गत समर्थित स्टार्टअप निवेशकों और उपयोगकताओं दोनों की ओर से बढ़ती रुचि आकर्षित कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर उद्यमों में परंपरागत रूप से राजस्व प्राप्त होने से पहले विकास की लंबी अवधि, पर्याप्त अनुसंधान एवं विकास निवेश और उच्च तकनीकी जोखिम शामिल होते हैं, जो अक्सर शुरूआती चरण के निवेशकों को सतर्क कर देते हैं। परिणामस्वरूप वर्ष 2021 से पहले देश में इस क्षेत्र में उद्यम पूंजी निवेश सीमित रहा।

सरकार की डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना जिसकी घोषणा वर्ष 2022 में की गई थी, वित्तीय सहायता, उन्नत ईडीए टूल्स, बौद्धिक संपदा कोर आदि तक पहुंच और सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन के बारे में व्यापक इकोसिस्टम जागरूकता प्रदान करके प्रारंभिक जोखिम को कम करने के माध्यम से इस चुनौती का समाधान करती है। स्टार्टअप्स को तकनीकी और उद्योग विशेषज्ञों से बनी एक सक्षम विशेषज्ञ समिति द्वारा कठोर स्क्रीनिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से शामिल किया जाता है, जिससे विश्वसनीय डीप-टेक कंपनियों को सहायता सुनिश्चित होती है। यह सुनियोजित हस्तक्षेप निवेशकों के विश्वास और व्यावसायिक व्यवहार्यता में लगातार सुधार करता है, जिससे निवेशक डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव समर्थित स्टार्टअप्स का सक्रिय रूप से मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित होते हैं।

सी2आई सेमीकंडक्टर्स

टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, नेशनल सेमीकंडक्टर और मैक्सिम इंटीग्रेटेड जैसी वैश्विक स्तर की अग्रणी कंपनियों में दशकों का अनुभव रखने वाली संस्थापक टीम द्वारा 5 जून 2024 को बेंगलुरु में स्थापित, सी2आई सेमीकंडक्टर्स को बाद में डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता और उन्नत चिप डिजाइन उपकरणों तक पहुंच के लिए 1 नवंबर 2024 से मंजूरी मिल गई।

सेमीकंडक्टर उद्योग के दिग्गज गणपति सुब्रमण्यम, जो याली कैपिटल के संस्थापक प्रबंध भागीदार हैं, के बोर्ड में शामिल होने के साथ, सी2आई की अगली पीढ़ी के एआई डेटा केंद्रों और क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पावर-मैनेजमेंट सेमीकंडक्टर समाधान विकसित कर रही है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 का उल्लंघन करने वाले खिलौने बेचने वाली ई-कॉमर्स संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की

भारतीय मानक ब्यूरो मानकों के अनुरूप न होने वाले खिलौनों की बिक्री के लिए स्नैपडील पर 5 लाख रुपए का जुमार्ना लगाया

(जीएनएस)। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने अनिवार्य खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हुए खिलौने बेचने वाले ई-कॉमर्स संस्थाओं और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस सम्बंध में, सीसीपीए ने स्नैपडील (ऐस वेक्टर लिमिटेड) पर अनुचित व्यापार तौर-तरीकों और भ्रामक विज्ञापनों का दोषी पाये जाने के कारण 5 पांच लाख रुपये का जुमार्ना लगाया है। स्नैपडील ने उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करते हुए अपने प्लेटफॉर्म पर बीआईएस मानकों के अनुरूप न होने वाले खिलौनों की बिक्री को बढ़ावा दिया था।

मुख्य आयुक्त श्रीमती निधि खरे और आयुक्त श्री अनुपम मिश्र के नेतृत्व में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य बीआईएस मानकों के अनुरूप न होने वाले खिलौनों की बिक्री के लिए स्नैपडील (ऐस वेक्टर लिमिटेड) के खिलाफ अंतिम आदेश जारी किया है।

सीसीपीए ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और पता लगाया कि स्नैपडील पर खिलौने , खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 का उल्लंघन करते हुए बेचे जा रहे थे जो 1 जनवरी, 2021 से अनिवार्य हो गया था। विस्तृत जांच में कई गंभीर खामियां सामने आईः

नियमों का निरंतर उल्लंघनः सूची से हटाए जाने के दावों के बावजूद, नियमों का उल्लंघन करने वाले खिलौने दिसंबर 2025 तक भी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहे।

बेचे गए उत्पादों से व्यावसायिक लाभः स्नैपडील ने केवल दो पहचाने गए विक्रेताओं - स्टैलियन ट्रेडिंग कंपनी और थ्रिफ्टकार्ट - के माध्यम से इन गैर-अनुरूप खिलौनों की बिक्री से 41,032 रुपए की फीस अर्जित की।

पारदर्शिता का अभावः कई सूचियों में निमार्ता का नाम, पता और अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन संख्या जैसी आवश्यक जानकारी का अभाव था।

अपर्याप्त उचित सावधानीः प्लेटफॉर्म ने स्वतंत्र सत्यापन के बिना पूरी तरह से विक्रेताओं की स्व-घोषणाओं पर भरोसा किया, इसे सीसीपीए ने खतरनाक उत्पादों की सूची को रोकने के लिए "अपर्याप्त" माना।

स्नैपडील ने अपना बचाव करते हुए कहा कि यह एक शॉपिंग मॉल की तरह "मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स इकाई" के रूप में कार्य करता है। सीसीपीए ने इस तुलना को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि स्नैपडील निम्नलिखित तरीकों से लेन-देन पर "पर्याप्त नियंत्रण" रखता हैः

"तूफान सेल" और "डील ऑफ द डे" जैसी प्लेटफॉर्म-व्यापी प्रचार बिक्री का प्रबंधन करना ।

"सर्वोत्तम मूल्य पर उत्कृष्ट गुणवत्ता" जैसे गुणवत्ता आश्वासन वाले टैग लगाना, जो कि बीआईएस मानक का पालन न करने वाले उत्पादों पर लागू होने पर झूठी गारंटी के रूप में कार्य करता है।

रसद, धनवापसी और प्रतिस्थापन योजनाओं को नियंत्रित करना।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण पता लगाया कि 'खरीददार सावधान रहे' से 'विक्रेता सावधान रहे' के सिद्धांत में बदलाव से उत्पाद सुरक्षा सुनिश्चित करने का भार विक्रेता और सुविधा प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म दोनों पर आ जाता है। परिणामस्वरूप, प्लेटफॉर्म की यह जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि सूचीबद्ध प्रत्येक उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है, जैसे कि खिलौनों के लिए बीआईएस प्रमाणन और पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाली किसी भी सेवा में कमी या माल में खराबी के लिए वह परोक्ष रूप से उत्तरदायी रहता है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 फरवरी को इजरायल का दौरा करेंगे, बोले बेंजामिन नेतन्याहू

(जीएनएस)।

यरूशलेमः इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 से 26 फरवरी तक दो दिवसीय यात्रा पर इजरायल आएंगे। उन्होंने यह घोषणा प्रमुख अमेरिकी यहूदी संगठनों के अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए की। नेतन्याहू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, "संसद में भाषण देने की तैयारी चल रही है। अगले सप्ताह यहां कौन आ रहा है? नरेंद्र मोदी।"

नेतन्याहू ने कहा, "इजराइल और भारत के बीच जबरदस्त गठबंधन है, और हम हर तरह के सहयोग पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब, आप जानते हैं, भारत कोई छोटा देश नहीं है। इसकी आबादी 1.4 अरब है। भारत बेहद शक्तिशाली और बेहद लोकप्रिय है।"

प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्राः प्वाइंटर्स में समझिए

प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में इजरायल की यह पहली

यात्रा होगी।

प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक, रक्षा और तकनीकी संबंधों को नई गति मिल सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी बार 2017 में इजराइल का दौरा किया था, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 25 साल पूरे होने का प्रतीक था।

पिछली यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू ने रक्षा, साइबर सुरक्षा, कृषि और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर बातचीत की थी।

इस बार, दोनों नेताओं के पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा करने की उम्मीद है।

सितंबर में दोनों देशों के बीच हुई थी ये संधि

दोनों देशों के बीच सितंबर में ही द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) हुई थी। इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर हस्ताक्षर हुए थे। इससे पहले पिछले साल नवंबर में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की इजरायल यात्रा के दौरान भी कई अहम समझौते हुए, जिसमें मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) और टीओआर पर हस्ताक्षर किए गए थे।

गौरतलब है कि भारत और इजरायल के बीच रिश्ते काफी मजबूत और मधुर रहे हैं। पीएम मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अच्छे मित्र हैं और एक-दूसरे से बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी की इजरायल यात्रा के बाद दोनों देशों को क्या-क्या फायदा मिलता है और क्या घोषणाएं होती हैं।

रोबोटिक्स एआई के माध्यम से मूल्यवर्धन करके स्वास्थ्य सेवा में एक नया आयाम जोड़ेगी: डॉ. जितेंद्र सिंह

डॉ. जितेंद्र सिंह का कहना है कि नई दिल्ली के एम्स के रेडियोलॉजिस्टों द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित टेली-रोबोटिक अल्ट्रासोनोग्राफी (टीयूएस) का संचालन करके अंटार्कटिका के मैत्री स्टेशन पर 12,000 किलोमीटर दूर तैनात लोगों की जांच करना, दूरस्थ स्वास्थ्य सेवा में एक नए युग की शुरूआत है

(जीएनएस)।

जितेंद्र सिंह ने दिल्ली से अंटार्कटिका तक लाइव टेली-रोबोटिक अल्ट्रासाउंड देखा, जो विज्ञान और सरकार के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अक्सर दोहराते हैं

नई दिल्ली, 16 फरवरीः कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित स्वास्थ्य सेवा और अत्याधुनिक विज्ञान में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित करते हुए, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने

आज अपने विचार व्यक्त किए।

केंद्रीय मंत्री नई दिल्ली स्थित एम्स को अंटार्कटिका के मैत्री अनुसंधान केंद्र से जोड़ने वाली स्वदेशी रूप से विकसित टेली-रोबोटिक अल्ट्रासोनोग्राफी प्रणाली के सफल लाइव प्रदर्शन को देख रहे थे।

राष्ट्रीय राजधानी में चल रही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर चचाओं का जिक्र करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस तरह के नवाचार एआई, रोबोटिक्स और वास्तविक समय की चिकित्सा विशेषज्ञता के संगम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा की पहुंच भौगोलिक बाधाओं से परे विस्तारित होती है।

नई दिल्ली एम्स और दिल्ली आईआईटी द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र के सहयोग से संयुक्त रूप से विकसित इस प्रणाली ने दिल्ली में बैठे एक डॉक्टर को अंटार्कटिका में 12,000 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित एक स्वयंसेवक की वास्तविक समय में अल्ट्रासाउंड जांच करने में सक्षम बनाया। अल्ट्रासाउंड प्रोब से सुसज्जित रोबोटिक भुजा छह डिग्री की स्वतंत्रता प्रदान करती है, जो एक विशेषज्ञ सोनोग्राफर के हाथों की सटीक गतिविधियों की हूबहू नकल करने में सक्षम है। बल-संवेदन सुरक्षा सुविधाओं और एक सेकंड से भी कम की देरी से प्रदान की जाने वाली नैदानिक रूप से विश्वसनीय इमेजिंग के साथ, यह प्रणाली आपातकालीन स्थिति में किए जाने वाले आकलन को सुगम बनाती है, जिसमें फास्ट स्कैन, पेट के अंगों का मूल्यांकन, हृदय संबंधी आकलन और आघात की जांच शामिल है।

दुर्गम और दूरस्थ वातावरणों के लिए डिजाइन की गई यह तकनीक, यह तय करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती है कि किसी मरीज का इलाज स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है या उसे स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से अंटार्कटिका में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां एयरलिफ्ट करना महंगा होने के साथ-साथ लॉजिस्टिक रूप से भी जटिल होता है। किफायती, मजबूत और विस्तार योग्य होने को ध्यान में रखते हुए निर्मित यह प्रणाली, सीमावर्ती क्षेत्रों, आपदा क्षेत्रों, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों और देश भर में मोबाइल चिकित्सा इकाइयों में तैनाती की क्षमता रखती है।

'सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव के लिए एआई का विस्तार: सार्वजनिक-निजी भागीदारी₹ विषय पर एक उच्च-स्तरीय पैनल चर्चा का आयोजन

(जीएनएस)।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026 के अंतर्गत "सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव के लिए एआई का विस्तारः सार्वजनिक-निजी भागीदारी" विषय पर एक उच्च-स्तरीय पैनल चर्चा का आयोजन किया।

भारत सरकार 16 से 20 फरवरी, 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026 की मेजबानी कर रही है। यह वैश्विक दक्षिण में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है। इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं, नीति निमार्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और नवप्रवर्तकों एक साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की परिवर्तनकारी क्षमता पर विचार-विमर्श करेंगे, जिसमें समावेशी और सतत विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा।

एक प्रमुख भागीदार मंत्रालय के रूप में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एक उच्च-स्तरीय पैनल चर्चा, प्रमुख पहलों के शुभारंभ और अपने समर्पित प्रदर्शनी स्टॉल पर एआई-संचालित स्वास्थ्य सेवा समाधानों के प्रदर्शन के माध्यम से शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली ने अभिलेखों के बुनियादी डिजिटलीकरण और बेहतर डेटा रिपोर्टिंग से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर परस्पर सुगम डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने याद दिलाया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभव मानक को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट के माध्यम से खुले मानकों, परस्पर सुगमता, गोपनीयता-आधारित डिजाइन और जनरेटिव एआई सहित उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने को

बढ़ावा देकर और कार्यान्वित किया गया।

उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्वास्थ्य के लिए एक मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में विकसित हो चुका है, जिसमें 859 मिलियन से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट खाते 878 मिलियन से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड से जुड़े हुए हैं। देश भर में 1.80 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म को एकीकृत किया जा रहा है। एआई-सहायता प्राप्त क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम द्वारा संचालित ई-संजीवनी ने 2.2 लाख से अधिक पंजीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के माध्यम से 449 मिलियन से अधिक टेलीकंसल्टेशन को सक्षम बनाया है, जिससे यह प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में विश्व की सबसे बड़ी टेलीमेडिसिन पहल बन गई है।

उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रणालियां सूचना के संग्रहण और प्रसारण को सक्षम बनाती हैं जबकि एआई इसकी बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्या और कार्रवाई को संभव बनाता है। उन्होंने कहा कि एआई में स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों पर बोझ कम करने और चिकित्सक-रोगी संबंध को मजबूत करने की क्षमता है, न कि उसे प्रतिस्थापित करने की।

उदाहरण देते हुए, उन्होंने एआई-आधारित डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग के लिए मधुनेत्रएआई, तपेदिक का पता लगाने के लिए एआई-सक्षम हैंडहेल्ड एक्स-रे और कफ अगेंस्ट टीबी (सीए-टीबी) जैसे ध्वनिक स्क्रीनिंग उपकरणों और तेजी से महामारी संबंधी अलर्ट के लिए एआई-एकीकृत निगरानी प्रणालियों का उल्लेख किया। उन्होंने एम्स दिल्ली, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ और एम्स ऋषिकेश में स्वास्थ्य सेवा में एआई के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना पर भी प्रकाश डाला।

सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने उद्योग और राज्य प्रतिनिधियों को सरकारी प्रणालियों के साथ काम करने, खरीद और डेटा ढांचे में सुधार करने और जमीनी स्तर पर सबसे उपयोगी एआई समाधानों की पहचान करने के अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में समावेश और समानता के साधन के रूप में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत का जोर, विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप, डिजिटल स्वास्थ्य और एआई के क्षेत्र में भारत की प्रगति का मार्गदर्शन करता रहेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ डॉ. सुनील कुमार बरनवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) स्वास्थ्य सेवा वितरण में दक्षता को काफी हद तक बढ़ा सकती है और विशेष रूप से बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में त्वरित, डेटा-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बना सकती है। उन्होंने कहा कि एआई-संचालित विश्लेषण लाभार्थियों की पहचान को मजबूत कर सकता है, दावों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर सकता है, धोखाधड़ी का पता लगा सकता है और सेवा उपयोग की निगरानी कर सकता है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और समग्र प्रणाली प्रदर्शन में सुधार होगा।

उन्होंने एआई समाधानों के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत डेटा प्रबंधन और गोपनीयता सुरक्षा उपायों द्वारा समर्थित अंतरसंचालनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के महत्व पर जोर दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के व्यापक और जटिल स्वरूप को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि संसाधनों के बेहतर आवंटन, सेवाओं के बेहतर लक्ष्यीकरण और देश भर में बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचार आवश्यक हैं।

इस पैनल में सरकार, उद्योग, बहुपक्षीय संगठनों और स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने के लिए एआई नवाचारों को व्यापक स्तर पर लागू करने पर विचार-विमर्श किया जा सके। चचाओं में भविष्यसूचक विश्लेषण, प्रारंभिक रोग पहचान, टेलीमेडिसिन, स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एआई का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मंत्रालय भारत मंडपम के हॉल 1 में स्टॉल संख्या 1.63 और 1.64 पर इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो-2026 में अपनी डिजिटल स्वास्थ्य और एआई पहलों का प्रदर्शन भी कर रहा है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों के साथ माननीय राष्ट्रपति जी से मिलकर उन्हें समिति का 13वाँ प्रतिवेदन सौंपा

समिति के कार्य में गति लाकर राजभाषा को और भी सशक्त व आधुनिक बनाने की दिशा में समिति ने बीते 6 वर्षों में राष्ट्रपति जी को 4 प्रतिवेदन सौंपे हैं, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों के साथ माननीय राष्ट्रपति जी से मिलकर उन्हें समिति का 13वाँ प्रतिवेदन सौंपा।

प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा 'आज संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों के साथ माननीय राष्ट्रपति जी से मिलकर उन्हें समिति का 13वाँ प्रतिवेदन सौंपा। समिति के कार्य में गति लाकर राजभाषा को और भी सशक्त व आधुनिक बनाने की दिशा में समिति ने बीते 6 वर्षों में राष्ट्रपति जी को 4 प्रतिवेदन सौंपे हैं, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है।

'नवाबों के शहर' लखनऊ पहुंचे सिद्धांत चतुर्वेदी...चढ़ा इश्क का खुमार, मृणाल ठाकुर संग शेयर कीं स्पेशल फोटोज

(जीएनएस)।

फिल्म 'दो दीवाने शहर में' संजय लीला भंसाली की प्रोडक्शन में बनी है. यह एक खूबसूरत लव स्टोरी है, जिसमें भावनाओं और रिश्तों की गहराई दिखाई गई है. कई दिनों से लगातार मृणाल और सिद्धांत फिल्म की प्रमोशन को लेकर लगे हुए हैं. दोनों ने वेलेंटाइन वीक के सारे डे साथ में मनाए थे, जिसे सोशल मीडिया पर काफी प्यार मिला था.

अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी इन दिनों आगामी फिल्म 'दो दीवाने शहर में' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. रोमांटिक ड्रामा फिल्म में वे मृणाल के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. अभिनेता हाल ही में लखनऊ की सैर पर गए हुए हैं. उन्होंने सोमवार को इंस्टाग्राम पर इसकी झलकियां शेयर कीं. इन तस्वीरों में वे अकेले लखनऊ की गलियों में घूमते दिख रहे हैं, तो कुछ फोटोज में उनकी को-स्टार मृणाल ठाकुर भी साथ नजर आ रही हैं. सिद्धांत ने इन तस्वीरों के साथ लिखा, "मुझे लखनऊ और घूमना है.

बस 4 दिन बाकी हैं."

सिद्धांत का यह पोस्ट फैंस को काफी पसंद आ रहा है. वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. फिल्म 'दो दीवाने शहर में' संजय लीला भंसाली की प्रोडक्शन में बनी है. यह एक खूबसूरत लव स्टोरी है, जिसमें भावनाओं और रिश्तों की गहराई दिखाई गई है. कई दिनों से लगातार मृणाल और सिद्धांत फिल्म की प्रमोशन को लेकर लगे हुए हैं. दोनों ने वेलेंटाइन वीक के सारे डे साथ में मनाए थे, जिसे सोशल मीडिया पर काफी प्यार मिला था.

फिल्म 'दो दीवाने शहर में' का निर्देशन रवि उद्यावर ने किया है. यह फिल्म दो ऐसे लोगों की कहानी है जो यह सिखाती है कि हर वक्त परफेक्ट होना जरूरी नहीं है. इसके कुछ गाने रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें दर्शकों की तरफ से काफी प्यार मिल रहा है. साथ ही, इसमें सिद्धांत और मृणाल की केमिस्ट्री भी सबको बहुत पसंद आ रही है. अब देखना होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में कैसा प्रदर्शन करेगी.

इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में हैं. इन दोनों के अलावा फिल्म में ईला अरुण, जॉय सेनगुप्ता, आयशा रजा, विराज गेहलानी, संदीपा धर, दीपराज राणा, मोना अम्बेगांवकर, अचिंत कौर, और नवीन कौशिक भी नजर आएंगे. अब देखना होगा कि फिल्म को दर्शक कितना प्यार देते हैं. रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'दो दीवाने शहर में' 20 फरवरी को रिलीज होगी.

खदरा लखनऊ व्यापार मंडल की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने ली शपथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत उपस्थित रहे ये लोग

(जीएनएस)।

लखनऊ के खदरा परिक्षेत्र में नौ व्यापार मंडलों का गठन किया गया, जिनके नवनियुक्त पदाधिकारियों ने शपथ ली। खदरा लखनऊ व्यापार मंडल परिक्षेत्र में नौ संगठनों का गठन किया गया है। नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह सीतापुर रोड के खदरा चुंगी में आयोजित किया गया। यहां उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, विधायक नीरज बोरा व महापौर सुषमा खर्कवाल भी उपस्थित रहीं।

खदरा परिक्षेत्र लखनऊ व्यापार मंडल के संरक्षक- मुसव्विर अली उर्फ मंशू (पार्षद), मो. सगीर खान, विधिक सलाहकार- विजय तिवारी, हामिद रज्जाक एवं प्रवक्ता- मो. असलम, दीनदयाल नगर खदरा लखनऊ व्यापार मंडल अध्यक्ष- विशाल,

वरिष्ठ उपाध्यक्ष- मो. तारिक उपाध्यक्ष, मजहर वरिष्ठ, महामंत्री- अनवार अली, शकील, मंत्री-संजय जैन, सचिव- अहमद, कोषाध्यक्ष-

मो. अशफाक, प्रचार मंत्री- उमेश अग्रवाल, संरक्षक- सरोज, सतीश ने शपथ ली।

अध्यक्ष- फैजान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष- मुस्तकीम, उपाध्यक्ष- मुदस्सिर, वरिष्ठ महामंत्री- शहजाद, महामंत्री- शारिक गाजी, मंत्री- मो. अरसलान, सचिव- निजाम, कोषाध्यक्ष- मो. हारून, दीपू गुप्ता, प्रचार मंत्री- शानू ने शपथ ली।

इसके अलावा शिवनगर रोड खदरा लखनऊ व्यापार मंडल अध्यक्ष- डॉ. शफीक अंसारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष- अनस, उपाध्यक्ष- शमशुल अंसारी, वरिष्ठ महामंत्री- अरविन्द कुमार, महामंत्री- बुद्धिसागर मिश्र, बड़ी पकरिया रोड खदरा लखनऊ व्यापार मंडल अध्यक्ष- इस्माईल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष- दीपू जायसवाल, उपाध्यक्ष- इस्तिखार, वरिष्ठ महामंत्री- अजीम, महामंत्री- आशीष वर्मा।

कर्बला रोड खदरा लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अंजुम वरिष्ठ, उपाध्यक्ष- शोएब सिद्दीकी, उपाध्यक्ष- बिलाल,

वरिष्ठ महामंत्री- फुरकान महामंत्री, अवध वाटिका रोड व्यापार मंडल अध्यक्ष- यूसुफ अंसारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष- शकील, उपाध्यक्ष- मो. शज्जू, वरिष्ठ महामंत्री- मो. आसिफ, महामंत्री- सादान मंत्री, सीतापुर रोड खदरा (पश्चिम) लखनऊ व्यापार मंडल अध्यक्ष- आशीष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष- रिजवान कुरैशी, उपाध्यक्ष- मो. आमिर, वरिष्ठ महामंत्री- राहुल, महामंत्री- शहनवाज आलम ने शपथ ली।

रामलीला ग्राउंड रोड खदरा लखनऊ व्यापार मंडल अध्यक्ष- आशीष जायसवाल , वरिष्ठ उपाध्यक्ष- इश्तियाक खान, उपाध्यक्ष- ध्रुव मिश्र, वरिष्ठ महामंत्री- मो. इदरीस, महामंत्री- शहाबुद्दीन।

सीतापुर रोड खदरा (पूरब) लखनऊ व्यापार मंडल

अध्यक्ष- राकेश कुमार गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष- जीलानी, उपाध्यक्ष- जीमल अहमद, वरिष्ठ महामंत्री- मुमताज, महामंत्री- सलमान ने पद की शपथ ली।

लखनऊः मेट्रो टिकट के लिए लाइन में लगने का झंझट खत्म, मोबाइल से बुक करें क्यूआर कोड और सीधे करें सफर

(जीएनएस)।

लखनऊ के मेट्रो यात्रियों के लिए सोमवार से एक नई सुविधा की शुरूआत हुई है. अब आपको टोकन के लिए लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने क्यूआर-आधारित टिकटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे यात्री घर बैठे ही मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक कर सकेंगे.

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (वढटफ्ठ) के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने सोमवार को हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर क्यूआर-आधारित टिकटिंग प्रणाली का औपचारिक उद्घाटन किया. इस नई व्यवस्था के तहत यात्री अब लखनऊ मेट्रो के आधिकारिक मोबाइल ऐप, टिकट वेंडिंग मशीन (ळश्ट) और टिकट काउंटर से क्यूआर टिकट बुक कर सकते हैं. मोबाइल ऐप से बुक किए गए टिकट डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध होंगे, जबकि काउंटरों से कागज वाले क्यूआर टिकट मिलेंगे. यात्री इन टिकटों को ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन (अत्रढ) गेट पर लगी पीली पट्टी वाले स्कैनर पर स्कैन करके स्टेशन के भीतर प्रवेश और निकास कर सकेंगे.

मोबाइल ऐप और टीवीएम से

मिलेगी सुविधा

लखनऊ मेट्रो प्रशासन ने सभी स्टेशनों पर नई क्यूआर-समर्थित टिकट वेंडिंग मशीनें (ळश्ट) स्थापित की हैं. इन मशीनों पर यात्रियों को यूपीआई (वढक) के जरिए भुगतान करने की सुविधा भी मिलेगी. जो लोग तकनीकी रूप से कम सहज हैं, वे टिकट काउंटर से पेपर-आधारित क्यूआर टिकट ले सकते हैं. खास बात यह है कि टोकन आधारित पुरानी व्यवस्था भी अन्य मशीनों पर पहले की तरह ही चालू रहेगी, जिससे यात्रियों के पास सफर के लिए कई विकल्प मौजूद होंगे.

डिजिटल इंडिया की ओर एक और कदम

इस अवसर पर एमडी सुशील कुमार ने कहा कि यह कदम 'स्मार्ट ट्रैवल' की अवधारणा पर आधारित है. यात्री अब कहीं से भी टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे यात्रा तेज और सुविधाजनक हो जाएगी. उन्होंने इसे 'डिजिटल इंडिया' के दृष्टिकोण के अनुरूप बताया, जहां सेवाएं सिर्फ 'एक टैप' की दूरी पर हैं. इस प्रणाली से स्टेशनों पर भीड़ कम होगी और यात्रियों का समय भी बचेगा. पीली पट्टी वाले एएफसी गेट्स को विशेष रूप से इन टिकटों की स्कैनिंग के लिए तैयार किया गया है.

जल्द शुरू होगी 'वन नेशन, वन कार्ड' सुविधा

कानपुर और आगरा मेट्रो के सफल मॉडल के बाद, अब लखनऊ में भी जल्द ही नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा शुरू की जाएगी. सुशील कुमार ने बताया कि अगले चरण में इस सुविधा के आने से यात्री देश भर के उन सभी मेट्रो सिस्टम में सफर कर सकेंगे जहां एनसीएमसी की सुविधा उपलब्ध है. यह 'वन नेशन, वन कार्ड' के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, जिससे यात्रियों को हर शहर के लिए अलग कार्ड रखने

पांच साल बाद एक बार फिर कोलकाता में रैली करेंगे पीएम मोदी, बंगाल चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी

पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावी तैयारियों के बीच ही, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी बुधवार को बंगाल के दौरे पर आने वाले हैं।

नई दिल्ली, (जीएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के दूसरे हफ्ते में पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। यहां वह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे ठीक 5 साल पहले मार्च, 2021 में इसी परेड ग्राउंड मैदान में जनसभा को संबोधित किया था।

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा 15 मार्च को हो सकती है। पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावी तैयारियों के बीच ही, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी बुधवार को बंगाल के दौरे पर आने वाले हैं।

अमित शाह कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां से वह मायापुर जाएंगे और इस्कॉन मंदिर में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। शाह इस्कॉन में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की 152वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे।

शाह अपने दौरे के दौरान संतों और भिक्षुओं के साथ बैठक कर सकते हैं। वह इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण की आरती करेंगे। इसे देखते हुए नादिया का जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क है।

रथ यात्राएं निकालेगी बीजेपी

बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक, पार्टी दक्षिण बंगाल के अलग-अलग जिलों में रथ यात्राओं का आयोजन करने की योजना बना रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने संकेत दिया है कि रथ यात्रा होली समारोहों के तुरंत बाद शुरू होगी और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर इनका समापन होगा। इसके लिए पार्टी नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं।

बीजेपी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र तैयार करने में जुटी है।

इस बार पार्टी ने एक ड्रॉप बॉक्स सिस्टम के जरिए जनता से उसकी राय ली है और उसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। इसके अलावा पार्टी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट भी तैयार कर रही है।

पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर उम्मीदवार तय होने के बाद इसे अंतिम फैसले के लिए केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा।

'रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव विश्लेषण' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी

वित्त मंत्रालय के वित्तीय विभाग ने चिंतन शिविर-2026 में "रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव विश्लेषण" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की

रिपोर्ट में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, भुगतान अवसंरचना को मजबूत करने और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में सरकार के प्रोत्साहन ढांचे की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है

(जीएनएस)।

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने 13-14 फरवरी 2026 को आयोजित चिंतन शिविर के दौरान "रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई (व्यक्ति-से-व्यापारी) लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव विश्लेषण" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

यह अध्ययन नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के परामर्श से एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष अनुसंधान एजेंसी द्वारा किया गया है। विश्लेषण में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, भुगतान अवसंरचना को मजबूत करने और देश भर में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में सरकार के प्रोत्साहन ढांचे की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है।

यह प्रोत्साहन योजना भारत सरकार के व्यापक नीतिगत उद्देश्यों के हिस्से के रुप में परिकल्पित की गई थी, जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को सार्वभौमिक रूप से अपनाना, नकदी पर निर्भरता कम करना और नियमित आर्थिक गतिविधियों को औपचारिक बनाना था। वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू की गई और वित्त वर्ष 2024-25 तक जारी रहने वाली इस योजना के अंतर्गत अधिग्रहण करने वाले बैंकों और इकोसिस्टम के प्रतिभागियों को संरचित बजटीय सहायता प्रदान की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डिजिटल भुगतान नागरिकों और व्यापारियों दोनों के लिए किफायती, सुलभ और टिकाऊ बना रहे।

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव विश्लेषण व्यापक प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसमें 15 राज्यों के 10,378 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया है, जिनमें 6,167 उपयोगकर्ता, 2,199 व्यापारी और 2,012 सेवा प्रदाता शामिल हैं। ये सभी भारत के डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम के प्रमुख हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा, गहन द्वितीयक शोध भी किया गया है। अध्ययन में शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को कवर करते हुए पांच भौगोलिक क्षेत्रों - उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर-पूर्व - को शामिल करते हुए एक व्यापक नमूनाकरण ढांचा अपनाया गया है।

सटीक, विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाले डेटा संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए 22 जुलाई से 25 अगस्त 2025 के बीच आमने -सामने कंप्यूटर-सहायता प्राप्त व्यक्तिगत साक्षात्कार का उपयोग करके फील्डवर्क किया गया।

लखनऊ कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल में आईएसआई का जिक्र; तीन दिन में दूसरा धमकी भरा मेल

लखनऊ, (जीएनएस)। लखनऊ कोर्ट को सोमवार सुबह ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसमें आईएसआई का जिक्र किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस, डॉग और बम स्क्वॉड ने कोर्ट परिसर में सघन तलाशी ली। तीन दिन में यह दूसरी धमकी है। हालांकि जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

कचहरी को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस बार भी धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई। धमकी भेजने वाले ने ईमेल में लिखा कि आपके कोर्ट के जज के चैंबर में 12 आरडीएक्स आईठडी लगाए गए हैं, जो जल्द ही फटेंगे। तमिलनाडू में ईम्ब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू हो से रोकें। दोपहर 12:15 तक सभी को खाली करा लें।

ईमेल सुबह करीब आठ बजकर 38 मिनट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेजी गई थी। इसके बाद सभी को अलर्ट कर दिया गया। राजधानी में कचहरी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्रवेश व निकास के गेट पर सुरक्षाकर्मी बढ़ा

दिए गए। छानबीन के दौरान कोई भी विस्फोटक नहीं मिला। अधिवक्ता व न्यायाधीश रोज की तरह अपना कार्य करते रहे। कचहरी काम प्रभावित नहीं हुआ। ईमेल में नीचे एलटीटीई और पाकिस्तानी आईएसआई का जिक्र भी किया गया था।

तीन दिन पहले भी आई थी मेल

तीन दिन पहले भी लखनऊ समेत 18 जिलों में एक ई-मेल से दहशत फैल गई थी। धमकी भरा मैसेज लखनऊ में जिला जज को ई-मेल से भेजा गया था। मैसेज मिलने के बाद फौरन कचहरी को खाली करा लिया गया। बम निरोधक दस्ते के बाद पुलिस टीम ने कचहरी में छानबीन की। हालांकि, वहां कोई बम नहीं मिला।

धमकी भेजने वाले ने लिखा था कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद दोपहर दो बजे कचहरी में धमाका किया जाएगा। अगर बचा सकते हो तो बचा लो। इस मामले की जानकारी वजीरगंज पुलिस को दी गई। इसके बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गईं। बड़ी संख्या में पुलिस बल कचहरी पहुंची।

इसके बाद अधिवक्ताओं को कचहरी खाली करने के लिए कहा गया। कचहरी से न्यायाधीश भी बाहर निकल गए। काफी देर तक छानबीन के बाद पता चला कि किसी ने शरारत की है। इसकी वजह से कोर्ट का काम भी प्रभावित हुआ। कचहरी के सभी गेटों पर सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए। इस मामले में कोर्ट नाजिर ने वजीरगंज थाने में ईमेल भेजने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

लखनऊः सिंधी समाज ने उठाई भगवान झूलेलाल जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की मांग, अन्य राज्यों का दिया हवाला

(जीएनएस)।

लखनऊ, लखनऊ के सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने भगवान झूलेलाल जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है।

भगवान झूलेलाल जयंती (चेटीचंड) पर उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश न होने से सिंधी समुदाय में निराशा है। सोमवार को इंदिरा नगर स्थित झूलेलाल भवन में चेटीचंड मेला कमेटी की कार्यकारिणी की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री से प्रदेश में छुट्टी घोषित करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।

बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे कई राज्यों में भगवान झूलेलाल जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रहता है। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी अवकाश की मांग को लेकर कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही

मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा।

पुरानी टीम पर भरोसा, नई नियुक्तियां

कमेटी की इस पहली बैठक में पुरानी टीम के पदाधिकारियों को उनके पदों पर बरकरार रखते हुए कुछ नए सदस्यों को भी शामिल किया गया है।

प्रवक्ता अशोक मोतियानी, अध्यक्ष रतन मेघानी, महामंत्री संजय जसवानी, और कोषाध्यक्ष सतेन्द्र भावनानी ने बताया कि समाज अपने इष्ट देव की जयंती 20 मार्च को भव्य रूप से मनाने की तैयारी में जुट गया है। इस अवसर पर सिंधी बाहुल्य क्षेत्रों से विशाल शोभायात्रा निकाली जाएगी।

बैठक में हंसराज राजपाल, राजू जसवानी, सतीश लखमानी, नीरज राजपाल, श्याम कृष्णानी, नितेश मध्यान, विक्की दयलानी, दिनेश रायचंदानी, प्रल्हाद गुरनानी, आनंद खत्री, सुरेश चबलानी, अमर नाथ चौधरी, मुकेश केवलानी, मनीष लालवानी, निखिल तोलानी, सूरज जसवानी और पुनीत लालचंदानी सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे।

लखनऊः 100 से ज्यादा लोगों के नाम पर करोड़ों का लोन फ्रॉड, यूपी एसटीएफ ने मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार

(जीएनएस)। लखनऊ में एसटीएफ और साइबर क्राइम टीम ने 100 से अधिक लोगों के नाम पर करोड़ों रुपये का फर्जी लोन पास कराने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड आमिर अहसन को गिरफ्तार किया है।

एसटीएफ और साइबर क्राइम थाने की संयुक्त टीम ने रविवार सुबह आईआईएम रोड स्थित सहारा होमर के पास से करोड़ों रुपये के लोन फ्रॉड गिरोह के मास्टरमाइंड आमिर अहसन को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरोह ने बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से 100 से अधिक लोगों के नाम पर फर्जी तरीके से लोन पास कराकर करोड़ों रुपये की ठगी की। इस मामले में पहले ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जानकीपुरम शाखा के मैनेजर गौरव सिंह समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कैसे हुआ लोन फ्रॉड?

हजरतगंज निवासी राज बहादुर गुरुंग ने शिकायत में बताया कि उनके परिचित इंद्रजीत के कहने पर उन्होंने वर्ष 2023 में अपना आधार और पैन कार्ड लोन पास कराने के नाम पर दिया था। उन्हें जानकीपुरम स्थित यूनियन बैंक शाखा ले जाया गया, जहां बैंक मैनेजर ने कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए। कुछ महीनों बाद उनके मोबाइल पर ईएमआई बकाया का मैसेज आया। जांच में पता चला कि उनके नाम पर 28 अप्रैल 2023 को 9.50 लाख रुपये का मुद्रा लोन और 10 मई 2023 को 1.50 लाख रुपये का कार लोन पास हो चुका था।

एसटीएफ के अनुसार, गिरोह आधार और पैन कार्ड पर लगी फोटो को एडिट कर अपने सदस्यों की फोटो लगाता था। फर्जी कंपनियों के नाम पर कोटेशन तैयार कर बैंक कर्मियों की साठगांठ से मुद्रा लोन स्वीकृत कराया जाता था। बाद में रकम हड़प ली जाती थी। गिरोह अलग-अलग बैंकों से 100 से अधिक व्यक्तियों, फर्मों और कंपनियों के नाम पर लोन लेकर करोड़ों रुपये का फ्रॉड कर चुका है।

मास्टरमाइंड की भूमिका

एएसपी विशाल विक्रम सिंह के मुताबिक, आमिर अहसन ने बीए करने के साथ ड्राफ्ट्समैन में डिप्लोमा किया है। 2018 में उसकी मुलाकात नावेद से हुई थी, जिसके बाद दोनों ने फर्जी लोन गिरोह की योजना बनाई। आरोपित के पास से एक मोबाइल फोन, आधार कार्ड, तीन क्रेडिट/डेबिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चार लग्जरी गाड़ियां जिसमें दो इनोवा क्रिस्टा, एक एक्सयूवी-500 और एक सियाज तथा नकदी बरामद की गई है।

एसटीएफ अब आरोपितों के बैंक खातों, वॉलेट और अन्य वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। जब जांच की भनक लगी तो एक अन्य आरोपी ने अपना लैपटॉप और मोबाइल नदी में फेंककर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की थी।

आगे की कार्रवाई

13 सितंबर 2025 को एसटीएफ ने गौरव सिंह समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार किया था। अब मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का फॉरेंसिक परीक्षण कराया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

कांग्रेस करेगी विस का घेराव, नेताओं को किया गया नजरबंद; लखनऊ के कांग्रेसियों को रोकने के लिए घरों पर पुलिस तैनात

(जीएनएस)।

कांग्रेस मंगलवार को मनरेगा के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी। मनरेगा के मुद्दे को लेकर कांग्रेस मंगलवार को विधानसभा का घेराव करेगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडेय व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में होने वाले विधानसभा के घेराव को टालने के लिए पुलिस ने 24 घंटे पहले से ही कांग्रेस नेताओं को उनके घरों पर नजरबंद करना शुरू कर दिया है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विशेष तौर पर बैरीकेडिंग कर दी है।

प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि मनरेगा केवल रोजगार योजना नहीं,

बल्कि ग्रामीण भारत की समग्र आर्थिक प्रणाली को चलाने वाला आधार स्तंभ है। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कांग्रेस द्वारा शुरू की गई इस योजना को केंद्र सरकार खत्म कर कर रही है। इसे बचाने के लिए कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया गया है।

विधानसभा के घेराव का किया है आह्वान

इसके तहत सभी जिले में चौपाल, धरना प्रदर्शन एवं लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने मंगलवार को विधानसभा घेराव के लिए प्रदेश भर के कांग्रेसी नेताओं व कार्यकताओं से विधानसभा घेराव का आह्वान किया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के विधानसभा घेराव के कार्यक्रम से डरी सरकार के इशारे पर कांग्रेस नेताओं को लखनऊ पहुंचने से रोकने के लिए उन्हें उनके घरों पर ही पुलिस की तैनाती कर नजरबंद किया जा रहा है।

लखनऊ में कंटेनर की टक्कर से चाय पीने निकले एमबीबीएस के छात्र की मौत, दुर्घटना में दोस्त घायल

(जीएनएस)।

लखनऊ। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे दो छात्रों को शनिवार की देर रात अज्ञात कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना में दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को एपेक्स ट्रामा सेंटर पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने बाइक चला रहे बिजनौर निवासी 23 वर्षीय ध्रुव अग्रवाल को मृत घोषित कर दिया। उनका साथी गंभीर रूप से घायल है।

बिजनौर के बस्सी कीरतपुर निवासी ध्रुव अग्रवाल राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र थे। वह मेरठ निवासी सहपाठी हार्दिक के साथ शहीद पथ स्थित संस्थान के हास्टल में रहते थे।

बाइक में मारी जोरदार टक्कर

ध्रुव के मौसेरे भाई मनीष अग्रवाल ने बताया कि शनिवार देर रात ध्रुव बुलेट बाइक से हार्दिक के साथ चाय पीने निकले थे। वह बाइक से शहीद

पथ की सर्विस लेन से अहिमामऊ की तरफ जा रहे थे। चौराहे से कुछ दूर पहले तेज रफ्तार अज्ञात कंटेनर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों लोग छिटककर सड़क पर जा गिरे।

बाइक सड़क पर कई मीटर घिसट गई। घटना में दोनों को गंभीर चोटें आई। राहगीरों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे अहिमामऊ चौकी इंचार्ज महेश कुमार सिंह ने दोनों घायलों को इलाज के लिए एपेक्स ट्रामा सेंटर भिजवाया।

चिकित्सकों ने ध्रुव को मृत घोषित कर दिया। हार्दिक को भी गंभीर चोटें आई हैं। उनका इलाज जारी है। इस बीच कंटेनर चालक घटनास्थल से फरार हो गया। सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर ने राजीव रंजन के मुताबिक, कंटेनर की तलाश जारी है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

बिजनौर के प्रतिष्ठित बर्तन व्यवसायी हैं पिता

मनीष ने बताया कि ध्रुव के पिता राजीव अग्रवाल बिजनौर जनपद के प्रतिष्ठित बर्तन व्यवसायी हैं। घटना के बाद से पिता, मां कविता और बड़े भाई देव अग्रवाल के आंसू नहीं थम रहे हैं।

पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे दोस्त

घटना के बाद ध्रुव के कई सहपाठी और संस्थान के प्रोफेसर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। दोस्तों ने

लखनऊ की पहचान से खिलवाड़, हेरिटेज जोन में अवैध पार्किंग, एलडीए वीसी बोले- कई बार लिखा पत्र

अवैध पार्किंग को लेकर छऊअ कई बार पुलिस और हुसैनाबाद ट्रस्ट को पत्र लिख चुका है. लेकिन समस्या जस की तस है.

(जीएनएस)।

लखनऊ : राजधानी की पहचान हुसैनाबाद हेरिटेज जोन से खिलवाड़ जारी है. यहां द लखनऊ म्यूजियम की शुरूआत 22 फरवरी से होगी. इस म्यूजियम के यहां होने के बाद भीड़ बढ़ेगी. लेकिन पार्किंग के अभाव में रूमी गेट के सामने अवैध पार्किंग बना दी गई है. सामने ही गुलाब वाटिका में पार्किंग बनाए जाने का बेहतर विकल्प है.

दूसरी ओर LDA यहां फूड कोर्ट के पास एक ओपन पार्किंग बनाने का ऐलान किया था. जिसकी टेंडर प्रक्रिया भी चल रही थी. लेकिन अब यहां छऊअ पार्किंग नहीं बाएगा. पार्किंग की व्यवस्था हुसैनाबाद ट्रस्ट करेगा. सवाल रूमी गेट के बाहर अवैध पार्किंग का है. इस अवैध पार्किंग को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण कई बार पुलिस और हुसैनाबाद ट्रस्ट को पत्र लिख चुका है. इसके बावजूद अब तक यहां अवैध पार्किंग है.

लखनऊ की पहचान से खिलवाड़.

समाजिक कार्यकर्ता हर्षल खत्री बताते हैं कि निश्चित तौर पर यहां बेहतर पार्किंग की जरूरत है. यह पार्किंग गुलाब वाटिका में बनाई जाए तो बेहतर होगा. उन्होंने बताया कि रूमी गेट के बाहर अवैध पार्किंग करना घोर अनुचित है. हर हाल में हेरिटेज जोन से अवैघ पार्किंग को हटाया जाए.

सामाजिक कार्यकर्ता शमील शम्शी बताते हैं कि मेरी लखनऊ विकास प्राधिकरण से बात हुई है. वहां से जानकारी मिली है कि निकट भविष्य में यह रास्ता बंद कर दिया जाएगा. इसके बाद पार्किंग की समस्या समाप्त हो जाएगी. लेकिन शमील शम्सी की बात का लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी खंडन कर रहे हैं.

रूमी गेट के बाहर अवैध तरीके से खड़ी गाड़ियां. रूमी गेट के बाहर अवैध तरीके से खड़ी गाड़ियां.

सामाजिक कार्यकर्ता ऋद्धि किशोर गौड़ ने बताया कि पहले तो यहां की कोबाल्ट रोड ने लोगों को परेशान किया हुआ है. इसके बाद में रूमी गेट की इस अवैध पार्किंग से भी बड़ी समस्याएं हो रही हैं. यहां से अवैध पार्किंग हटाई जानी चाहिए. इसके बाद हेरिटेज जोन का असली मतलब निकलेगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, छऊअ की तरफ से पहले यहां ओपन पार्किंग के लिए एक टेंडर किया गया था. वह प्रक्रिया पूरा नहीं हो सकी. अब यहां ओपन पार्किंग की व्यवस्था हुसैनाबाद ट्रस्ट की ओर से की जाएगी. हुसैनाबाद ट्रस्ट ही ओपन पार्किंग का संचालन करेगा. रूमी गेट के बाहर जो पार्किंग है वह पूरी तरह से अवैध है और हम कई बार प्रशासनिक स्तर पर इसको लेकर बात कर चुके हैं कि इसको यहां से हटाया जाना चाहिए.